भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1007
दिनांक 31 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न

पशुओं के लिए चारे की कमी

1007. श्री एस. कल्याणसुन्दरमः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसानों को पेश आ रही पशुओं के चारे की कमी की जानकारी है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश भर में पशुओं के चारे के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में घोषित योजनाओं का ब्यौरा क्या है और तमिलनाडु राज्य के लिए जिला-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) जी हां, देश में चारे की कमी है। आईसीएआर-भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान (आईजीएफआरआई), झांसी ने अनुमान लगाया है कि देश में हरे और सूखे चारे की क्रमशः 11.24-32% और 23% कमी है।

(ख) और (ग) भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग वर्ष 2014-15 से आहार एवं चारा विकास संबंधी उप-मिशन के साथ केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन को लागू करके राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को संपूरित कर रहा है। चारे की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से जुलाई, 2021 में इस योजना को निम्नलिखित घटकों के साथ पुनर्संरेखित किया गया है, अर्थात्,

(i) गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता,
(ii) चारा संबंधी उद्यमिता विकास कार्यक्रम
(iii) गैर-वनीय बंजर भूमि/रेंजलैंड/चारागाह/गैर-कृषि योग्य भूमि से चारा उत्पादन।
(iv) वन भूमि से चारा उत्पादन।

उपर्युक्त के अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू), 100 एफपीओ, मुख्य रूप से चारा केंद्रित एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के माध्यम से केंद्रीय सेक्टर योजना "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन" को लागू कर रहा है।

भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान (आईजीएफआरआई झांसी-आईसीएआर) ने भी तमिलनाडु सहित 25 राज्यों के लिए चारा संसाधन विकास योजना तैयार की है, ताकि राज्यों में उनके फसल पैटर्न और पशुधन प्रजातियों के आधार पर चारे की उपलब्धता बढ़ाई जा सके।

तमिलनाडु सरकार के पास मौजूद 1552.16 लाख रुपये की अव्ययित शेष राशि को देखते हुये, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पुनर्संरेखित राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत तमिलनाडु सरकार को कोई निधियां आवंटित नहीं की गईं।

****